भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- **277**

दिनांक **19** जुलाई, **2022** के लिए प्रश्न

डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि

277. श्री मारगनी भरत:

श्रीमती कविता मलोथू:

डॉ.जी. रणजीत रेड्डी:

डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) के अंतर्गत आने वाले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गांवों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त दोनों राज्यों में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा लाभार्थी को दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान डीआईडीएफ के माध्यम से वर्ष-वार और जिले-वार किसानों को होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग)क्या सरकार उक्त ऋण पर कोई ब्याज सहायता प्रदान कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ)क्या सरकार के समक्ष डीआईडीएफ के तहत ऋण के लिए कोई आवेदन लंबित हैं और यदि हां, तो वे कितने समय से लंबित हैं और क्या मंत्रालय द्वारा लंबित आवेदनों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क)परियोजना कार्यान्वयन अवधि के अंत तक आंध्र प्रदेश में कुल 910 गांव और तेलंगाना में 1100 गांव लाभन्वित होंगे।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन अवधि के अंत तक आंध्र प्रदेश में कुल 1.22 लाख उत्पादक सदस्य और तेलंगाना में 0.73 लाख उत्पादक सदस्य लाभान्वित होंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एनडीडीबी द्वारा संवितरित ऋण का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	करोड़ रू. में				
		2019-20	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	कुल
आंध्र प्रदेश						
1.	संगम उत्पादक कंपनी	16.60	18.13	0.00	---	**34.73**
तेलंगाना						
2.	मुलुकानूर महिला दुग्ध संघ	---	---	4.60	0.80	**5.40**
कुल		**16.60**	**18.13**	**4.60**	**0.80**	**40.13**

(ग) भारत सरकार पात्र ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायता प्रदान कर रही है। 31.05.2022 तक, इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 64.59 करोड़ रू. की राशि ब्याज सहायता के रूप में जारी की गई।

(घ) डीआईडीएफ के तहत, एनडीडीबी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की परियोजना मंजूरी समिति (पीएससी) की सिफारिश पर नाबार्ड द्वारा परियोजनाएं संस्वीकृत की जाती हैं। डीआईडीएफ योजना के तहत एनसीडीसी के विचारार्थ लंबित प्रस्तावों का विवरण अनुबंध में दिया गया है। विभाग, एनडीडीबी और एनसीडीसी द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा करता है।

******

अनुबंध

डीआईडीएफ योजना के तहत विचारार्थ लंबित प्रस्तावों का विवरण

1. एनडीडीबी के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।
2. एनसीडीसी द्वारा विचारार्थ लंबित प्रस्तावों का विविरण इस प्रकार है:

लाभार्थी	राज्य	उद्देश्य	करोड़ रू. में		स्थिति
			परियोजना लागत	ऋण राशि	
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ	मध्य प्रदेश	आईएमएल मुद्रित प्लास्टिक जार पैकेजिंग संयंत्र की स्थापना	10.60	8.48	एनसीडीसी द्वारा प्रस्ताव की जांच पड़ताल की गई और आगे कार्रवाई करने के लिए लाभार्थी से परियोजना संबंधित विवरण और वित्तीय जानकारी मांगी गई। उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक नियमित रूप से लाभार्थी के साथ संपर्क में है।
भोपाल दुग्ध संघ	मध्य प्रदेश	20 एमटीपीडी दुग्ध पाउडर संयंत्र की स्थापना	6 2.40	49.92	प्रस्ताव विचाराधीन है। एनसीडीसी की प्रतिभूति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनसीडीसी राज्य के निर्धारित गारंटी प्रारूप की जांच कर रहा है। जांच के बाद, परियोजना के क्षेत्रीय मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
राजस्थान राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, (राजफेड)	राजस्थान	100 एमटीपीडी गोपशु आहार संयंत्र की स्थापना	13.22	9.09	एनसीडीसी द्वारा प्रस्ताव की जांच पड़ताल की गई और आगे कार्रवाई करने के लिए लाभार्थी से परियोजना संबंधित विवरण और वित्तीय जानकारी मांगी गई। उत्तर की अभी भी प्रतीक्षा है। संबंधित क्षेत्रीय निदेशक नियमित रूप से लाभार्थी के साथ संपर्क में है।